दैनिक जागरण
शतरंज की तरह जीवन में भी दूरदर्शिता की ही विजय होती है

निर्णायक कार्रवाई की प्रतीक्षा

कश्मीर में सुरक्षा बलों पर हुए अब तक के सबसे बड़े आतंकी हमले के बाद इस हमले को अंजाम देने वाले जैश ए मोहम्मद के संरक्षक पाकिस्तान को केवल चेतावनी ही नहीं दी गई, बल्कि उसे प्रदान किए गए सर्वाधिक तरजीही राष्ट्र के दर्जे को भी छीन लिया गया। इसके बावजूद यह कहना कठिन है कि इससे पाकिस्तान की सेहत पर कोई असर पड़ेगा। वैसे भी यह तो वह मांग थी जो एक लंबे अर्से से की जा रही थी। पाकिस्तान को सर्वाधिक तरजीही राष्ट्र के दर्जे से वंचित करने के साथ ही कूटनीतिक संबंधों के स्तर में भी कमी लाई जाई जानी चाहिए। इसके अतिरिक्त सिंधु जल समझौते को रद करने के बारे में भी सोचा जाना चाहिए। कूटनीतिक उपायों के जरिये पाकिस्तान को दंडित करने के साथ ही चीन को भी कोई सख्त संदेश देने की जरूरत है। वह जैश-ए मोहम्मद के सरगना का खुला बचाव करके भारतीय हितों के खिलाफ ही काम कर रहा है। चीन को यह बताया जाना चाहिए कि वह न केवल वुहान में बनी समझ-बूझ के खिलाफ काम कर रहा है, बल्कि पाकिस्तान की ढाल बनकर शत्रु सरीखे रवैये का परिचय दे रहा है। इसमें संकोच इसलिए नहीं किया जाना चाहिए, क्योंकि आज भारत को चीन की जितनी जरूरत है उससे ज्यादा उसे भारत की है। भारत एक बार फिर पाकिस्तान के हाथों लहूलुहान इसीलिए हुआ, क्योंकि एक के बाद एक आतंकी हमलों के बाद भी यह अपेक्षा की गई कि बातचीत के जरिये उसे सही रास्ते पर लाया जा सकता है। यह अपेक्षा कमजोरी के अलावा और कुछ नहीं। बीते करीब दो दशकों का इतिहास यही बताता है कि कैसे पाकिस्तानी सेना और उसकी खुफिया एजेंसी की ओर से पाले-पोसे आतंकी हमें आतंकित करते हैं और फिर भी हम उसके साथ बातचीत की संभावनाएं तलाशने लगते हैं।

पुलवामा से बड़ा हमला मुंबई में किया गया था, लेकिन जरूरी सबक सीखे बगैर भारत कुछ समय बाद ही पाकिस्तान के साथ वार्ता की मेज पर दिखा। यही कहानी बाद में भी दोहराई जाती रही। इसके दुष्परिणाम सामने आने ही थे। निःसंदेह जरूरत केवल इस बात की ही नहीं है कि पाकिस्तान के खिलाफ ऐसे कदम उठाए जाएं जिससे उसकी सेहत पर असर पड़े और वह अपनी शैतानी हरकतों से बाज आए। इसी के साथ यह भी जरूरी है कि कश्मीर घाटी के हालात पर भी गंभीरता से ध्यान दिया जाए। यह सही है कि वहां के हालात पाकिस्तान के कारण बिगड़े हैं, लेकिन आखिर उन्हें ठीक करने की जिम्मेदारी तो भारत की ही है। कश्मीर में आतंक समर्थक तत्वों के साथ उन्हें संरक्षण देने वालों के खिलाफ निर्णायक कार्रवाई समय की मांग है। इस कार्रवाई की जद में वह राजनीतिक तबका भी आना चाहिए जो कभी हुर्रियत सरीखी भाषा बोलता है और कभी पाकिस्तान से बातचीत को जरूरी समझता है। इसीलिए पाकिस्तान वहां दखल देने में समर्थ है। स्पष्ट है कि उन कारणों का निवारण होना ही चाहिए जिनके चलते पाकिस्तान को कश्मीर में दखल देने में आसानी होती है। बेहतर होगा कि पाकिस्तान के खिलाफ निर्णायक कार्रवाई पर विचार करते समय कश्मीर में भी निर्णायक कदम तय कर लिए जाएं।

दवाओं के सैंपल फेल

हिमाचल दवा उत्पादन में उत्तर भारत में सबसे अग्रणी है। फार्मा उद्योग सबसे अधिक सोलन जिले के बद्दी, सिरमौर, ऊना व कांगड़ा जिलों में स्थापित हैं। किसी भी उद्योग की विश्वसनीयता उसके उत्पाद के आधार पर ही होती है। यह चिंता का विषय है कि प्रदेश में बनने वाली दवाओं के 14 सैंपल मानकों के अनुरूप सही नहीं पाए गए हैं। केंद्रीय दवा मानक नियंत्रण संगठन की ओर से जनवरी में देशभर में कई स्थानों से लिए दवाओं के सैंपल में से 45 उद्योगों के सैंपल में खोट पाया गया है। विडंबना यह है कि अधिकतर दवाएं दिल के रोग, अस्थमा, एलर्जी, एंटीबॉयोटिक एवं खांसी जुकाम की हैं। यह ऐसी दवा है जो हर घर में आज किसी न किसी रूप में इस्तेमाल की जाती है। ऐसी दवा में खोट होना सीधे-सीधे लोगों की सेहत से खिलवाड़ है। बार-बार ऐसे मामलों में हिमाचल के दवा उद्योगों के नाम की मौजूदगी प्रदेश की छवि पर भी बुरा प्रभाव डालती है। केंद्रीय दवा मानक नियंत्रण संगठन की ओर से अलर्ट जारी होने के बाद राज्य दवा नियंत्रक की ओर से संबंधित सभी दवा उद्योगों को नोटिस जारी कर दिए गए हैं। नोटिस में दवा की गुणवत्ता खराब होने का कारण पूछा गया है एवं स्टॉक वापस मंगवाने का आदेश दिया गया है। उसके बाद देशभर से खराब बैच नंबर की दवाओं को नष्ट किया जाएगा, लेकिन सवाल यह है कि दवा जैसे संवेदनशील उत्पाद के निर्माण में कोताही क्यों बरती जा रही है। दवा के सैंपल फेल होने वाले कारकों की तलाश करके इस दिशा में कदम उठाने की पहल की जाए ताकि बार-बार इस तरह के मामले सामने न आएं। स्वास्थ्य विभाग के साथ-साथ दवा नियंत्रक की ओर से जब तक इस मामले में सख्ती नहीं बरती जाएगी, तब तक इस तरह की लापरवाही सामने आती रहेगी। इसलिए जरूरी है कि ऐसे उद्योगों पर शिकंजा कसा जाना चाहिए। निगरानी का तंत्र इतना मजबूत होना चाहिए कि पूर्ण रूप से संतुष्ट होने के बाद ही दवाओं की खेप कारखानों से बाहर जाए। सरकार ने बेशक दवाओं के बैच वापस लाने का आदेश दिया गया है, लेकिन यह स्पष्ट नहीं है कि इसकी निगरानी कौन कर रहा है।

आतंक के खिलाफ लंबी लड़ाई का वक्त

सी उदय भास्कर

पुलवामा हमले का सबक यह है कि भारत आतंकवाद से निपटने के लिए दीर्घकालिक और उद्देश्यपरक रणनीति विकसित करे

जम्मू-कश्मीर के पुलवामा जिले में केंद्रीय रिजर्व पुलिस बल (सीआरपीएफ) के काफिले पर हुआ आत्मघाती हमला कश्मीर घाटी में पिछले दो दशकों में भारतीय सुरक्षा बलों पर सबसे बड़ा आतंकवादी हमला है। इसमें करीब 40 जवानों की जान चली गई और कई अन्य गंभीर रूप से घायल हो गए। इस बर्बर हमले की जिम्मेदारी प्रतिबंधित आतंकी संगठन जैश ए मोहम्मद ने ली है। आत्मघाती हमलावर की पहचान स्थानीय युवक आदिल अहमद डार के रूप में हुई है, जिसने सीआरपीएफ के काफिले की एक बस से विस्फोटकों से भरी अपनी कार को भिड़ा दिया। इस काफिले में करीब 80 गाड़ियां शामिल थीं। इस हमले से देश की जनता को बहुत पीड़ा पहुंची है। वह आतंकवादियों को पनाह देने वालों और जाहिर है कि पाकिस्तान के खिलाफ आक्रोशित भी है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कड़ी कार्रवाई करने का वादा किया है। उन्होंने कहा है कि सरकार ने बदला लेने के लिए सुरक्षा बलों को खुली छूट दे दी है। उन्होंने यह भी कहा है कि पाकिस्तान को दुनिया में अलग-थलग किया जाएगा। भारत ने इसकी शुरुआत भी कर दी है। केंद्र सरकार ने सख्त कदम उठाते हुए पाकिस्तान से सर्वाधिक तरजीही राष्ट्र यानी एमएफएन का दर्जा वापस ले लिया है। यह अंतरराष्ट्रीय व्यापार नियमों के तहत दोनों देशों के बीच कारोबार को आसान बनाने के लिए भारत ने उसे दे रखा था। पुलवामा हमले की अमेरिका, रूस, फ्रांस, जर्मनी और अन्य प्रमुख ताकतों ने भी एक सुर में निंदा की है, पर यह ध्यान रहे कि चीन दबे स्वर में पाकिस्तान का समर्थन करता रहा है। चीन संयुक्त राष्ट्र सुरक्षा परिषद में जैश ए मोहम्मद और उसके आकाओं को अपने वीटो से जिस तरह से बचाता रहा है उसे भला कौन भूल सकता है?

पुलवामा में हुआ हमला भारत पर हुआ पहला आतंकी हमला नहीं है। जैश ए मोहम्मद ने नवंबर 1999 में जम्मू-कश्मीर में पहला फिदायीन हमला किया था। पुलवामा की यह दूसरी ऐसी घटना है जिसमें जैश ने आत्मघाती हमलावर का प्रयोग किया। वह जिस तरह से ऐसे हमलों लिए स्थानीय युवाओं को प्रेरित कर रहा है वह बेहद चिंतित करने वाला है। इस हमले के जवाब में भारत की ओर से कुछ सामरिक कार्रवाई हो सकती है। नियंत्रण रेखा के पार भी कुछ सैन्य कार्रवाई की उम्मीद की जा सकती है, पर पुलवामा सरीखे आतंकवादी हमलों के रोकने के लिए देश को दीर्घकालिक रणनीति विकसित करनी होगी। भारत कश्मीर में 1990 के आरंभिक दिनों से ही पाकिस्तान के छद्म युद्ध का सामना कर रहा है। यही वह समय था जब पाकिस्तान की सेना और खुफिया एजेंसी आइएसआइ ने आतंकवादी गतिविधियों के जरिये भारतीय सेना और नागरिकों को निशाना बनाना शुरू किया था। इससे लड़ने का भारत का रिकॉर्ड मिला-जुला रहा है। इसमें कोई दो राय नहीं कि आने वाले दिनों में जटिल चुनौतियां कम होने वाली नहीं हैं, क्योंकि एक परमाणु ताकत होने से साथ-साथ पाकिस्तान को चीन और इस्लामी जगत के अधिकांश देशों का समर्थन भी प्राप्त है। ऐसे में भारत को अपनी सुरक्षा नीतियों पर पुनर्विचार करने और उन्हें आक्रामक ढंग से फिर से तय करने की जरूरत है।

अवधेश राजपूत

यह भी ध्यान रहे कि आतंकवाद और पाकिस्तान को लेकर देश की घरेलू राजनीति बेहद जटिल है। यह दुख की बात है कि पुलवामा हमले के रूप में राष्ट्रीय सुरक्षा के समक्ष गंभीर चुनौती के वक्त भी प्रमुख राजनीतिक दलों में एका नहीं है और सब अलग-अलग सुर में बोल रहे हैं। शायद उनकी नजर में आगामी चुनाव है जिसमें वे सुरक्षा खामियों को मुद्दा बनाकर राजनीतिक लाभ उठा सकते हैं, लेकिन यह ध्यान रहे कि पुलवामा का यह हमला हमारे लिए बड़ा सबक ले कर आया है। जरा हमले की प्रकृति देखें। शुरुआती जांच में जो तथ्य सामने आए हैं उनके अनुसार हमले में 300 किलोग्राम विस्फोटक भरी एक कार का उपयोग किया गया और वह सुरक्षा बलों के काफिले तक आसानी से पहुंच गई। यह निश्चित रूप से सुरक्षा में चूक है जिसकी जांच सक्षम एजेंसियां करेंगी। एक सवाल यह भी है कि क्या यह खुफिया तंत्र की विफलता की देन है? कहा जा रहा है कि एक अपुष्ट रिपोर्ट थी जिसके अनुसार जैश ए मोहम्मद और कश्मीर घाटी में उसके समर्थक जनवरी के अंत या फरवरी के आरंभ में बड़े हमले की योजना बना रहे हैं। जिस प्रकार गणतंत्र दिवस का आयोजन शांतिपूर्वक बीत गया उससे लगता है कि आतंकी सुरक्षा बलों को चौंकाना चाहते थे।पुलवामा हमले के प्रतिकार स्वरूप भारत की ओर से कुछ सामरिक कदम अवश्यंभावी है, लेकिन देश के सामने सबसे गंभीर चुनौती एक समग्र राष्ट्रीय रणनीति बनाने की है जिसमें राजनीति, सुरक्षा तंत्र, सामाजिक-आर्थिक क्षेत्र और सबसे महत्वपूर्ण नागरिकों की सक्रिय भागीदारी हो ताकि अन्य स्थानीय युवा आदिल अहमद डार के रास्ते पर न चलें।

अभी जम्मू-कश्मीर में राजनीतिक हालात बहुत उत्साहजनक नहीं है। भाजपा-पीडीपी का गठजोड़ का टूटना इसका सूचक है। पुलवामा हमले के शुरुआती कुछ घंटों में राजनीतिक दलों और उनके नेताओं के बीच जिस तरह आरोप-प्रत्यारोप की गाली-गलौज भरी जुबानी जंग देखने को मिली वह खेदजनक है। देश के आक्रोश को नेताओं द्वारा इस तरह अनर्गल बयानबाजी के जरिये जाया नहीं किया जाना चाहिए। भावनाएं भड़काना राष्ट्रवाद का बेजा इस्तेमाल है। पेचीदा कश्मीर मुद्दे का दीर्घकालिक समाधान जम्मू-कश्मीर की सामाजिक-राजनीतिक परिधि, दिल्ली और श्रीनगर के बीच और भारत-पाकिस्तान एवं चीन के बीच निहित है। दरअसल चीन ने जिस तरह से पाकिस्तान और उसके आतंकी समूहों और उसकी बर्बर नीतियों को समर्थन देने का रुख अपनाया हुआ है वह सबसे बड़ी बाधा है। चीन का यह रवैया नई दिल्ली के लिए एक स्थायी चुनौती है। इससे फर्क नहीं पड़ता कि प्रधानमंत्री कौन है।

एक बात लगातार कही जाती रही है कि जिहादी आतंकवादियों द्वारा थोपे गए छद्म युद्ध से भारत को खुद पार पाना होगा। भारत को पाकिस्तान और जिहादी आतंकवाद के प्रति अपनी नीति को स्थायित्व प्रदान करने के साथ उसे उद्देश्यपरक भी बनाना होगा। ऐसा करते समय आवेग और भावना में बहने से बचना होगा। इसके कुछ बाहरी पक्ष भी होने चाहिए। दीर्घकालिक राजनीतिक-कूटनीतिक रणनीति के तहत दिल्ली द्वारा प्रमुख विदेशी ताकतों और पड़ोसी देशों को जोड़ा जाना चाहिए। इससे ही इस्लामाबाद को विश्व मंच पर अलग-थलग करने में आसानी होगी। यह भी देखना होगा कि क्या चीन अपना नकारात्मक रवैया छोड़ने के लिए तैयार हो सकता है? निःसंदेह जरूरत आंतरिक सुरक्षा में व्यापक बदलाव लाने की भी है। 1999 में करगिल युद्ध के समय खुफिया तंत्र सहित आंतरिक सुरक्षा ढांचे में आमूलचूल परिवर्तन करने की आवश्यकता बताई गई थी। विडंबना है कि 20 साल पूर्व की सिफारिश अभी लागू होने की बाट जोह रही है। हमें अपनी इस अक्षमता और सुस्ती को तोड़ना होगा, क्योंकि यह जन-धन की क्षति का करण बन रही है।

(लेखक सोसायटी फॉर पॉलिसी स्टडीज के निदेशक हैं)

response@jagran.com

बड़े खतरे का हिस्सा है पुलवामा हमला

दिव्य कुमार सोती

इस बार हमारी कार्रवाई ऐसी होनी चाहिए जिसे पाकिस्तान की जनता देख और महसूस कर पाए

कश्मीर में सीआरपीएफ के काफिले को पाकिस्तान आधारित आतंकी संगठन जैश ए मोहम्मद ने तब निशाना बनाया जब 2500 से अधिक सीआरपीएफ जवान जम्मू से श्रीनगर जा रहे थे। इसे पुलवामा हमले के तौर पर जाना जा रहा है। पाकिस्तान समर्थित आतंकियों का उद्देश्य सुरक्षाबलों और देश के मनोबल को चोट पहुंचाना था। उड़ी हमले के जवाब में भारतीय सेना द्वारा सीमा पार अंजाम दी गई सर्जिकल स्ट्राइक और ऑपरेशन ऑल आउट में एक के बाद एक आतंकी कमांडरों के मारे जाने से कश्मीर में जिहादी आतंकी तंत्र मनोवैज्ञानिक दबाव में था। यह मानने के पर्याप्त कारण हैं कि पुलवामा हमला इस दबाव से आतंकी काडर को उबारने के लिए अंजाम दिया गया। पुलवामा हमले के बाद लश्कर ए तैयबा ने बयान जारी कर जैश ए मोहम्मद की तारीफ की और पाकिस्तान ने जैश ए मोहम्मद को संरक्षण देने के भारत के आरोप को खारिज किया। पुलवामा हमले का सामरिक परिप्रेक्ष्य कहीं ज्यादा बड़ा है। दरअसल तीन सीधे युद्धों में भारत से पटखनी खाने के बाद जनरल जिया उल हक ने अफगानिस्तान में कठपुतली सरकार बैठाने और भारत के खिलाफ छद्म युद्ध छेड़ने की ठानी थी। अफगानिस्तान को अपनी मुट्ठी में रखने का फैसला इसलिए लिया गया था ताकि भारत से किसी बड़े युद्ध की स्थिति में पाक फौज को पीछे हटने की जगह मिल सके। इसी दौरान सोवियत संघ के अफगानिस्तान पर हमले के चलते अमेरिका को शीत युद्ध के उस दौर में पाकिस्तान की मदद लेनी पड़ी और पाकिस्तानी सेना की खुफिया एजेंसी आइएसआइ ने अमेरिकी पैसे से आतंकी तैयार करके अफगानिस्तान भेजे, जो गुरिल्ला युद्ध में सोवियत सेना को वापस जाने के लिए मजबूर करने में कामयाब रहे। सोवियत संघ के विघटन के बाद अमेरिका की दिलचस्पी अफगानिस्तान और पाकिस्तान में खत्म हो गई।

अफगानिस्तान में सोवियत संघ पर विजय ने जिहादी आतंकवाद को इस दंभ से भर दिया कि उन्होंने उस महाशक्ति को धूल चटा दी जिसे अमेरिका नहीं हरा पा रहा था। इसी दौर में 1989 में पाकिस्तान ने कश्मीर में इन जिहादी आतंकियों को भारत के खिलाफ इस्तेमाल करना शुरू किया। इसी के साथ कश्मीर में आतंकवाद की शुरुआत हो गई। 1996 में पाकिस्तान ने मौके का पूरा फायदा उठाते हुए अफगानिस्तान में तालिबान के जरिये सत्ता पर कब्जा जमा लिया। आतंकियों को एक पूरा देश मिल गया तो विश्व भर से जिहादी आतंकी वहां इकट्ठे होने लगे। आइएसआइ की सरपरस्ती में ओसामा बिन लादेन को भी वहां शरण दी गई और भारतीय विमान के अपहरण के जरिये मौलाना मसूद अजहर को छुड़वा लिया गया। इसके बाद अमेरिका 9/11 से दो-चार हुआ।

चूंकि अमेरिका ने पाकिस्तान को साथ न देने की स्थिति में पाषाण युग में पहुंचा डालने की धमकी दी इसलिए मजबूरी में पाकिस्तान ने ऊपरी तौर पर अमेरिका का साथ दिया, लेकिन अफगानिस्तान से भागे आतंकियों को अपने यहां शरण देना जारी रखा। इसमें लादेन भी शामिल था। एक ओर अमेरिका अफगानिस्तान में तालिबान से लड़ता रहा और दूसरी ओर आइएसआइ पाकिस्तान के कबीलाई इलाकों में फैले मदरसों और आतंकी ट्रेनिंग कैंपों में नए आतंकी तैयार कर अफगानिस्तान भेजता रही। नतीजा यह हुआ कि 18 साल से चल रही लड़ाई के बावजूद अफगानिस्तान के बड़े इलाके पर तालिबान का वर्चस्व है।

अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप को लगता है कि अफगानिस्तान में उलझे होने से अमेरिका की शक्ति कुंद हो रही है। वह अमेरिकी सेना को अफगानिस्तान से निकालकर अमेरिकी शक्ति का फिर से संचय करना चाहते हैं। वह अफगानिस्तान से अमेरिकी सेना को वापस बुलाने का ऐलान कर चुके हैं और अमेरिकी सरकार के प्रतिनिधि तालिबान लड़ाकों से बातचीत कर रही है। अमेरिका बस यह गारंटी चाहता है कि तालिबान अफगानिस्तान में उसके खिलाफ साजिश रचने वालों को शरण न दे। अमेरिका एक तरह से अफगानिस्तान को पाकिस्तान के हवाले करने का ही काम कर रहा है। अमेरिका के इसी रवैये के चलते पाकिस्तानी सेना और आइएसआइ के साथ-साथ उसके साये में पल रहे जैश एवं लश्कर जैसे आतंकी संगठनों को लगता है कि वे सोवियत संघ के बाद अब अमेरिका को भी पस्त करने में कामयाब होने वाले हैं। अफगानिस्तान से अमेरिका के निकलते ही वहां तालिबान, हक्कानी नेटवर्क और आइएसआइ का वर्चस्व होगा। इसके बाद अंदेशा यही है कि अमेरिकी फौज से उलझे जिहादी संगठन भारत पर निशाना साधेंगे। अफगानिस्तान में भारतीयों के लिए खतरा बढ़ेगा और आइएसआइ को कश्मीर में आतंक की आग को भड़काने के लिए ज्यादा फुरसत और संसाधन मिलेंगे। ऐसे में आने वाले दिनों में भारत को आतंकवाद के नए और लंबे दौर का सामना करना पड़ सकता है।

पुलवामा हमले के बाद प्रधानमंत्री मोदी ने कहा कि आतंकवादियों और उनके आकाओं ने बहुत बड़ी गलती कर दी है और उन्हें इसकी बड़ी कीमत चुकानी पड़ेगी। जाहिर है सरकार पाकिस्तान समर्थित आतंकियों पर किसी बड़ी कार्रवाई का मन बना चुकी है। दूसरी सर्जिकल स्ट्राइक की चर्चा भी है। इस बार वह शायद बहुत अच्छा विकल्प न हो, क्योंकि इस बार पाकिस्तान चौकन्ना होगा। ध्यान रहे कि उस दौरान पाकिस्तान ने अपनी जनता के बीच यही प्रचारित किया था कि कहीं कोई सर्जिकल स्ट्राइक नहीं हुई। ऐसे में इस बार हमारी कार्रवाई ऐसी होनी चाहिए जिसे पाकिस्तान की जनता देख और महसूस कर पाए। यह मनोवैज्ञानिक युद्ध है और पाकिस्तान को वैसा ही मनोवैज्ञानिक घाव मिलना चाहिए जैसा उसने भारत को देने की कोशिश की है।

इसका कोई औचित्य नहीं कि मौलाना मसूद अजहर और हाफिज सईद जैसे आतंकी सरगना पाकिस्तान में सुरक्षित रहें और हमारे जवान अपने ही देश में असुरक्षित। हमारे पास ऐसे सैन्य विकल्प मौजूद हैं जिनके द्वारा बिना सीमा पार किए और पूर्ण युद्ध छेड़े भी हम पाकिस्तान को सबक सिखा सकते हैं। वैसे भी वायु और नौसैनिक शक्ति में पाकिस्तान हमारे सामने कहीं नहीं टिकता। हमें यह याद रखना चाहिए कि जिन आतंकी संगठनों और सरगनाओं को सजा देने की हमने ठान ली है वे पहले ही अंतरराष्ट्रीय बिरादरी द्वारा प्रतिबंधित हैं। ऐसे में भारतीय कार्रवाई की सूरत में पाकिस्तान के पास बहुत ज्यादा सैन्य विकल्प नहीं हैं और जो हैं भी उनसे निपटने में हमारी सेनाएं पूर्णतयाः सक्षम हैं। ऐसे में जरूरी है कि भारत के खिलाफ नए सिरे से आतंकी युद्ध छेड़ने के पाकिस्तान के मंसूबों को शुरुआती दौर में ही नाकाम कर दिया जाए।

(लेखक काउंसिल फॉर स्ट्रेटेजिक अफेयर्स से संबद्ध सामरिक विश्लेषक हैं)

response@jagran.com

ऊर्जा

वैराग्य

अनेक लोग यह मानते हैं कि जिसने अपना घर-द्वार छोड़ दिया, वही वैरागी है, लेकिन सच यह है कि घर-परिवार छोड़कर जंगल में चले जाने मात्र से वैराग्य नहीं मिलता। बाकायदा गृहस्थ-संसारी जीवन में भी वैरागी बना जा सकता है। जिस समय मनुष्य यह जान लेता है कि यह जो दुनिया वह देख रहा है, वह मिथ्या है, उसे एक न एक दिन नष्ट हो जाना है और उसका शरीर भी सिर्फ मिट्टी है तो वह व्यक्ति उसी क्षण वैराग्य को पा लेता है। इसके बाद उसे न अपना घर छोड़ने की जरूरत है और न ही भगवा कपड़े पहनने की जरूरत होती है। जंगल में कुटिया बनाकर रह रहे एक साधु के यहां एक महात्मा पधारे। साधु के यथोचित सत्कार से प्रसन्न होकर जब महात्मा ने उनसे विदा ली तो साधु बोले कि महात्मा जी, आपको मेरी कुटिया कैसी लगी? महात्मा ने जवाब दिया कि साधु महाराज आपकी कुटिया वाकई बहुत सुंदर है, लेकिन अब आप घर-परिवार त्याग चुके हैं तब कुटिया के प्रति आपका मोह उचित नहीं है। महात्मा की बात सुनकर साधु को अपनी भूल का अहसास हुआ।

दरअसल वैराग्य को समझने के लिए यह बात ही काफी है कि मनुष्य इस प्रश्न का उत्तर खोज ले कि वह खाने के लिए जी रहा है या जीने के लिए खा रहा है। इसी तरह एक सवाल और है कि आपका शरीर आप से संचालित है या आप शरीर से। रात होने लगे तो जरूरी नहीं कि वैरागी को नींद आने ही लग जाए, बल्कि जब आवश्यकता समझता है, तब सोता है, वह नींद का गुलाम नहीं है। मनुष्य जीवन में ऐसी उपलब्धियां ही वैराग्य का दर्पण होती हैं। सच कहा जाए तो वैराग्य की पहली शर्त ही यही होती है। वैराग्य जीवन और जगत को झुठलाने का नाम नहीं है, बल्कि इन्हें समझने और जीने की प्रक्रिया है।

स्वामी विवेकानंद कहते हैं कि बहुत से लोग स्वयं बड़े अज्ञानी हैं, फिर भी अहंकार से अपने को सर्वज्ञ समझते हैं। यह सोचना कि मेरे ऊपर कोई निर्भर है और मैं किसी का भला कर सकता हूं तो यह अत्यंत दुर्बलता का चिह्न है। यह अहंकार ही समस्त वैराग्य और आसक्ति की जड़ है और इससे ही समस्त दुखों की उत्पत्ति होती है। यह अहंकार अज्ञानता से आता है। इसलिए मनुष्य को सबसे पहले ज्ञान की ओर बढ़ना चाहिए।

आचार्य अनिल वत्स

सोलहवीं लोकसभा की उपलब्धि

सिद्धार्थ शंकर गौतम

गत पांच वर्षों में लोकसभा ने 200 विधेयक पारित किए, जबकि पिछली संप्रग सरकार में पारित विधेयकों की संख्या 181 थी

भारी-खींचतान के बावजूद सोलहवीं लोकसभा आजाद भारत की सर्वश्रेष्ठ लोकसभा रही। पांच वर्षों में लोकसभा ने 200 विधेयक पारित किए, जबकि पिछली संप्रग सरकार में पारित विधेयकों की संख्या 181 थी। सोलहवीं लोकसभा के 17 सत्रों में 85 प्रतिशत कार्य हुआ, जबकि आठ सत्रों में 100 प्रतिशत की उत्पादकता रही। शून्यकाल में भी पिछली लोकसभा के मुकाबले 97 प्रतिशत अधिक मामले उठाए गए। लोकसभा का 52 प्रतिशत समय विधायी कामकाज में लगा। पांच वर्ष में सरकार ने 1400 से अधिक अप्रासंगिक कानून समाप्त किए। सरकार ने जहां एक ओर भ्रष्टाचार रोधी, कालाधन, जीएसटी और गरीब सवर्णों को आरक्षण जैसे अहम विधेयक पारित करवाए वहीं तीन तलाक और नागरिकता जैसे विशेष विधेयक विपक्ष की नकारात्मक राजनीति की भेंट चढ़ गए। तीन तलाक और नागरिकता बिल पर राज्यसभा में सर्वाधिक खींचतान रही। दो बार अध्यादेश लाने के बाद भी इन विधेयकों को राज्यसभा से पारित नहीं होने दिया गया। सोलहवीं लोकसभा इसलिए भी याद रहेगी, क्योंकि पहली बार 44 महिला प्रतिनिधि इसका हिस्सा बनीं। भाजपा सरकार में भी महिला प्रतिनिधित्व सर्वाधिक रहा।

वर्तमान लोकसभा में 1984 के बाद 2014 में किसी राजनीतिक दल को पूर्ण बहुमत मिला था। भाजपा को 282 सीटें मिलीं जो बहुमत से 10 अधिक थीं। राजग गठबंधन को मिलाकर उसका आंकड़ा 336 तक पहुंच गया, जबकि विपक्ष के पास महज 207 सीटें थीं। प्रमुख विपक्षी दल कांग्रेस महज 44 सीटों पर सिमट गई। यह सदन की सीटों की कुल संख्या का दस प्रतिशत से भी कम था इसलिए उसे नेता प्रतिपक्ष का पद भी नहीं मिला। अतः सोलहवीं लोकसभा को जहां मजबूत सत्तापक्ष के लिए याद किया जाएगा, वहीं कांग्रेस की न्यूनतम सीटों एवं विपक्ष के नेता नहीं होने के लिए भी याद रखा जाएगा। नेता प्रतिपक्ष विहीन इस लोकसभा में सत्ता पक्ष की मजबूत उपस्थिति ने लोकतंत्र के प्रति निष्ठा दिखाते हुए सभी वर्ग, धर्म, संप्रदाय के लोगों के लिए सर्वोत्तम करने का प्रयास किया।

हालांकि सोलहवीं लोकसभा के अंतिम दो वर्ष भाजपा के लिए भी आत्मचिंतन के रहे। 2014 के आम चुनाव के बाद 27 लोकसभा सीटों पर उपचुनाव हुए जिनमें वह कोई नई सीट नहीं जीत पाई। इन 27 लोकसभा सीटों में से 13 सीटें उसकी खुद की थीं जिसमें से वह पांच सीटें दोबारा हासिल कर पाई और आठ सीटें हार गई। इस दौरान तृणमूल कांग्रेस ने अपनी चार सीटों, टीआरएस ने दो, आरजेडी, बीजेडी, एनपीपी और एनपीएफ ने अपनी एक सीट फिर से जीत दर्ज कीं। सपा ने एक सीट दोबारा जीती और दो सीटें भाजपा से छीनी। रालोद और एनसीपी ने भाजपा से अपनी सीटें पुनः प्राप्त कीं। वहीं इतिहास के अपने सबसे खराब दौर से गुजर रही कांग्रेस ने एक सीट दोबारा जीती और चार सीटें भाजपा से छीनी। खासकर उत्तर प्रदेश में भाजपा को अपनी गोरखपुर सीट भी विपक्षी एकता के आगे खोनी पड़ी। उम्मीद की जानी चाहिए कि आगामी सरकार भी जनहितैषी कार्यों को जारी रखना होगी ताकि नए भारत के निर्माण का खाका बुलंद हो सके।

(लेखक स्वतंत्र टिप्पणीकार हैं)

मेलबाक्स

मोदी का विकल्प प्रस्तुत करे विपक्ष

'मोदी के मुकाबले कौन' शीर्षक से लिखे अपने लेख में राजनाथ सिंह सूर्य ने मोदी विरोध के नाम पर एकजुट होने की कवायद करने वाले विपक्षी दलों से जो प्रश्न किया है, विपक्ष को उसका जवाब जरूर देना चाहिए। देश के विपक्षी दलों में मोदी विरोध को लेकर जैसी अकुलाहट दिखाई दे रही है, उससे एक बात तय है कि शरद पवार, चंद्रबाबू नायडू, ममता बनर्जी, मायावती और अरविंद केजरीवाल जैसे अति महत्वाकांक्षी राजनेता केवल प्रधानमंत्री बनने की चाहत में अपनी वर्चस्वता साबित करने की कोशिश करते दिखाई दे रहे हैं। उधर इन सबके द्वारा उपेक्षित कांग्रेस एकला चलो की मुद्रा में खड़ी नजर आ रही है। कांग्रेस अध्यक्ष द्वारा मोदी विरोध के लिए हद दर्जे का झूठ और अपशब्दों का प्रयोग करने के बाद भी जब प्रधानमंत्री मोदी की लोकप्रियता प्रभावित नहीं हुई तो राहुल गांधी को सहयोग देने के लिए प्रियंका वाड्रा को राजनीति में उतारा गया। इससे पूरे देश में यही संदेश गया है कि अब कांग्रेस के पास दूसरी पंक्ति का कोई इतना समक्ष नेता नहीं है जो राहुल गांधी को सहारा दे सके। लोकतंत्र में सत्ता पक्ष के क्रियाकलापों की समालोचना कर, उसके अनुचित कार्य की उचित पटल पर आलोचना करना विपक्ष की जिम्मेदारी है। लेकिन विपक्ष का यह कार्य पूरी तरह से सकारात्मक और देशहित में होना चाहिए। अभी तक संसद से सड़क तक राफेल विमान सौदे पर होने वाली बहस में सुप्रीम कोर्ट और कैग की सकारात्मक दृष्टि को नकारते हुए, प्रमुख विपक्षी दल कांग्रेस ने जैसी नकारात्मकता प्रदर्शित की है, वह हैरान करने वाली है। विपक्ष यदि एकजुट होकर सही मायने में मोदी का विरोध करना चाहता है तो उन्हें देशहित में मोदी से बेहतर विकास योजनाओं का मॉडल देश के समक्ष प्रस्तुत करते हुए प्रधानमंत्री के रूप में मोदी का विकल्प भी बताना चाहिए। जब तक ऐसा नहीं होता है तब तक विपक्षी एकजुटता का कोई महत्व नहीं है।

डॉ. वीपी पाण्डेय, अलीगढ़

श्रीलंका से सीखे भारत

जम्मू-कश्मीर के हालात से निपटने के लिए भारत को श्रीलंका से सीखना चाहिए। कश्मीर के हालात इतने खराब नहीं हैं, जितने की जाफना के थे। वहां आतंकी संगठन लिट्टे ने श्रीलंका को अपने आगे घुटने टेकने पर मजबूर कर दिया था। लिट्टे के पास अपनी वायुसेना थी, एयरपोर्ट थे, नौसेना थी। यहां तक कि एक बार तो लिट्टे ने कोलंबो एयरबेस पर हमला करके श्रीलंका के 75 प्रतिशत लड़ाकू विमानों को नष्ट कर दिया था। हर रोज कोलंबो में बम धमाके होते थे। लिट्टे के लड़ाके अब तक के सबसे जुनूनी लड़ाके माने जाते हैं, जो कि मानव बम बनते थे और साथ में सायनाइड का कैप्सूल भी रखते थे ताकि पकड़े जाने पर मौत को गले लगा सकें। उन्होंने श्रीलंका के कई नेताओं की हत्याएं की थीं। श्रीलंका के आधे हिस्से पर इनका कब्जा था। फिर ऐसे हालातों में महिंदा राजपक्षे ने सत्ता संभाली। उन्होंने पहले तो लिट्टे को श्रीलंका में भीतर तक आने दिया। लिट्टे वाले उनकी रणनीति समझ नहीं सके। फिर अचानक तीन तरफ से श्रीलंका की सेना ने धावा बोला। एक रिपोर्ट के मुताबिक इस कार्रवाई में एक लाख से ज्यादा लोग मारे गए। नतीजा यह हुआ कि श्रीलंका से लिट्टे का पूरी तरह से सफाया हो गया। फिर भारत जैसा देश क्या नहीं कर सकता है। बस जरूरत है महिंदा राजपक्षे जैसी इच्छाशक्ति की।

rkcomputers@gmail.com

कब तक शहीद होंगे जवान

देश के जवानों की शहादत प